एक अक्टूबर से एफडी के नियमों में बदलाव, आरबीआई ने जारी किए नए निर्देश

बैंकों में सावधि जमा से जुड़े नियमों में बदलाव का असर ग्राहकों और जमाकर्ताओं पर पड़ेगा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से सावधि जमा यानी एफडी से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। इन बदलावों का संबंध बैंकों में जमा राशि और सावधि जमा से जुड़े प्रावधानों से है।

आरबीआई समय-समय पर बैंकिंग व्यवस्था में जमा और निकासी से संबंधित नियमों में बदलाव करता है। सावधि जमा के मामले में भी ग्राहकों की सुविधा और बैंकिंग प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए नए प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। एफडी बैंक में निश्चित अवधि के लिए जमा की जाने वाली राशि होती है। इस पर बैंक निर्धारित ब्याज देता है। सामान्य बचत खाते की तुलना में एफडी में राशि एक तय अवधि के लिए रखी जाती है। समय से पहले राशि निकालने की स्थिति में बैंक के नियम लागू होते हैं।

नए नियमों के लागू होने के बाद सावधि जमा से संबंधित प्रक्रियाओं में बदलाव देखने को मिलेगा। इसका असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा, जो बैंक में नई एफडी कराने की तैयारी कर रहे हैं या पहले से सावधि जमा रखते हैं। आरबीआई के निर्देशों के तहत बैंकों को नए प्रावधानों के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं और ग्राहकों को दी जाने वाली जानकारी में आवश्यक बदलाव करने होंगे। इससे एफडी कराने वाले ग्राहकों के लिए नियमों को समझना और जमा राशि से संबंधित प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा।

बैंक ग्राहक एफडी कराने से पहले ब्याज दर, अवधि, समय से पहले निकासी के नियम और परिपक्वता से जुड़े प्रावधानों की जानकारी ले सकते हैं। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले बदलावों के बाद बैंकिंग संस्थानों को आरबीआई के नए नियमों का पालन करना होगा।

भारत 10 प्रतिशत से अधिक आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है: सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि भारत 10 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और नवाचार को बड़े पैमाने पर अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। सीतारमण ने आईआईटी मद्रास एलुमनाई एसोसिएशन के 'संगम 2026' कार्यक्रम में बातचीत के दौरान कहा कि 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर हासिल करना संभव है। उन्होंने कहा कि अधिक आर्थिक वृद्धि से आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की यात्रा को गति देने में मदद मिलेगी। इसके लिए सभी पक्षों की ओर से व्यापक प्रयास की जरूरत होगी। वित्त मंत्री ने वर्ष 2015 के बाद स्टार्टअप के तेजी से विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में वे अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

अमेरिकी अधिकारी बोले- अंतिम मुद्दों पर बातचीत जारी, जल्द समझौते की उम्मीद

न्यूयॉर्क, एजेंसी: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर अमेरिका की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिका के एक वरिष्ठ विदेश विभाग अधिकारी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर 90 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। अब कुछ अंतिम मुद्दों पर बातचीत चल रही है। अधिकारी के अनुसार, दोनों पक्ष समझौते के काफी करीब हैं और जल्द ही इसे लेकर घोषणा हो सकती है।

अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि व्यापार समझौता भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर तक ले जा सकता है। उन्होंने व्यापार को दोनों देशों के संबंधों में लंबे समय से प्रमुख मुद्दा बताया। उनके अनुसार, अंतिम चरण के मुद्दों पर सहमति बनने के बाद समझौते को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर टैरिफ, बाजार पहुंच और भारतीय उत्पादों के लिए शुल्क संबंधी प्रावधानों पर बातचीत हुई है। भारत की ओर से अपने निर्यातकों के लिए अनुकूल शुल्क व्यवस्था और घरेलू क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखने पर जोर दिया गया है। समझौते का अंतिम स्वरूप तय होने के बाद ही विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।

अमेरिकी अधिकारी ने अक्टूबर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत यात्रा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रहे संपर्क का हिस्सा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिसंबर में अमेरिका में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद भी जताई गई है। अधिकारी ने क्वाड के तहत भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते संपर्क का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठकें लगातार हो रही हैं।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे यानी आईएमईसी को भी अमेरिका और भारत की प्राथमिकता बताया गया। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, मध्य पूर्व की परिस्थितियों के कारण परियोजना की गति प्रभावित हुई है। क्षेत्र में स्थिरता आने के बाद इसके काम में तेजी आने की उम्मीद है। फिलहाल भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम रूप से हस्ताक्षरित नहीं हुआ है। 90 प्रतिशत से अधिक काम पूरा होने की जानकारी अमेरिकी अधिकारी के बयान पर आधारित है और शेष मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है।

खास-खबरें

मोनेको में प्रति व्यक्ति आय दो करोड़ रुपये के करीब, लग्जरी जीवन के लिए मशहूर देश

मोनाको, एजेंसी: यूरोप का छोटा देश मोनेको अपनी ऊंची प्रति व्यक्ति आय और आलीशान जीवनशैली के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहां महंगी संपत्तियां, लग्जरी कारें और समुद्र के किनारे बने आलीशान घर आम दृश्य हैं। देश की प्रति व्यक्ति आय करीब दो करोड़ रुपये सालाना के आसपास बताई जाती है, जिसके कारण मोनेको को दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है।

मोनेको का क्षेत्रफल बेहद छोटा है, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था का आकार और प्रति व्यक्ति आय काफी अधिक है। देश की अर्थव्यवस्था में वित्तीय सेवाओं, पर्यटन, रियल एस्टेट और लग्जरी कारोबार की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां दुनिया के कई धनी लोग रहते हैं और बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी संपत्ति खरीदते हैं।

मोनेको की राजधानी मोनाको-विले सहित प्रमुख इलाकों में महंगे अपार्टमेंट और समुद्र के किनारे स्थित संपत्तियों की कीमत बहुत अधिक है। सीमित जमीन और लगातार बनी रहने वाली मांग के कारण यहां रियल एस्टेट बाजार दुनिया के महंगे बाजारों में शामिल है। देश की पहचान लग्जरी कारों और बड़े आयोजनों से भी जुड़ी है। मोनेको में आयोजित होने वाली फॉर्मूला-1 ग्रां प्री दुनिया की प्रमुख मोटर रेसिंग प्रतियोगिताओं में शामिल है। इस आयोजन के दौरान देश में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। मोनेको में पर्यटन भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समुद्र तट, कैसीनो, होटल और महंगे रेस्तरां पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। देश की वित्तीय सेवाएं भी अर्थव्यवस्था को मजबूती देती हैं।

रविवार को खुलेंगी बैंक शाखाएं, 28 से 30 सितंबर तक रहेगी हड़ताल

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण महीने के आखिरी सप्ताह में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। बैंकों ने ग्राहकों को हड़ताल शुरू होने से पहले जरूरी बैंकिंग काम निपटाने की सलाह दी है, ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 28 सितंबर से तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद हैं। इसके बाद 27 सितंबर को रविवार की छुट्टी होने के बावजूद बैंक शाखाएं खुलेंगी। इसके बाद 28 से 30 सितंबर तक लगातार तीन दिन बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित रहने की संभावना है।

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों सहित कुछ पुराने निजी बैंकों ने ग्राहकों को हड़ताल से पहले आवश्यक बैंकिंग कार्य पूरे करने की सलाह दी है। ग्राहकों को भेजे संदेश में 27 सितंबर को शाखाएं खुली रहने की जानकारी दी गई है। बैंक यूनियनों ने पांच दिन के बैंकिंग कार्य सप्ताह को लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया है। तीन दिवसीय हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं में नकद जमा और निकासी, चेक समाशोधन तथा अन्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। जिन ग्राहकों को शाखा में जाकर बैंकिंग से जुड़े कार्य कराने हैं, उन्हें हड़ताल के दौरान परेशानी हो सकती है। इसलिए बैंकों ने ग्राहकों को आवश्यक लेनदेन और अन्य जरूरी काम पहले ही निपटाने की सलाह दी है।

डीएचएल एक्सप्रेस भारत में एक जनवरी से माल ढुलाई शुल्क में 8.9 फीसदी की करेगी बढ़ोतरी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दुनिया की सबसे बड़ी और अग्रणी अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता कंपनी डीएचएल एक्सप्रेस ने शनिवार को कहा कि वह भारत में माल ढुलाई शुल्क में 8.9 फीसदी वृद्धि करेगी, जो एक जनवरी 2027 से लागू होगी। डीएचएल एक्सप्रेस ने एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक यह वार्षिक मूल्य समायोजन वैश्विक स्तर पर बढ़ते हुए परिचालन खर्चों को संतुलित करने के लिए किया गया है। सालाना शुल्क में यह वृद्धि मुद्रास्फीति के दबाव, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और उद्योग-विशिष्ट लागतों में वृद्धि जैसे विभिन्न कारकों की वजह से की जाएगी।

आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने रखीं 174 सुधारों की शर्तें

इस्लामाबाद, एजेंसी: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता कार्यक्रम के तहत कई सुधार लागू करने के लिए कहा है। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर के ऋण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 174 विधायी और नीतिगत बदलाव करने होंगे। आईएमएफ ने आर्थिक स्थिरता, वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कदमों को जरूरी बताया है। आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच चल रहे कार्यक्रम के तहत सरकार को कई क्षेत्रों में बदलाव करने होंगे। इनमें वित्तीय प्रबंधन, कर व्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्र और सरकारी संस्थानों से जुड़े सुधार शामिल हैं। आईएमएफ का मानना है कि इन सुधारों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिलेगी और वित्तीय घाटे को नियंत्रित किया जा सकेगा। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार, महंगाई, ऊर्जा लागत और राजकोषीय दबाव जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। आईएमएफ के साथ हुए समझौते के तहत पाकिस्तान को आर्थिक नीतियों में बदलाव करने और तय लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता है।

सीएआईटी ने 'नो यूपीआई डे' की खबरों को बताया गलत

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने 2 अक्टूबर को देशभर में 'नो यूपीआई डे' मनाने की खबरों को गलत और भ्रामक बताया है। संगठन ने स्पष्ट किया कि उसने इस संबंध में न तो कोई निर्णय लिया है और न ही कोई प्रस्ताव या आधिकारिक घोषणा की है। सीएआईटी ने कहा कि उसके नाम से ऐसी खबरें प्रसारित करना तथ्यात्मक रूप से गलत है।

सीएआईटी के अनुसार, कुछ क्षेत्रीय और स्थानीय व्यापारिक संगठन यूपीआई पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के मुद्दे पर अपने स्तर पर विरोध कार्यक्रम कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों को सीएआईटी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। संगठन ने मीडिया से अपील की है कि उसके नाम से कोई भी जानकारी प्रकाशित करने से पहले आधिकारिक स्रोत से तथ्यों की पुष्टि की जाए। साथ ही व्यापारियों और आम लोगों से भी आधिकारिक बयानों पर भरोसा करने को कहा गया है।

- 2 अक्टूबर को देशव्यापी बहिष्कार का कोई ऐलान नहीं
- स्थानीय संगठन अपने स्तर पर कर सकते हैं विरोध

दरअसल, 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू किया जाना है। यह शुल्क व्यापारी से लिया जाएगा और 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन पर इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई भुगतान पर यह शुल्क लागू नहीं होगा। इस शुल्क को लेकर कुछ व्यापारिक संगठनों ने विरोध की घोषणा की थी। महाराष्ट्र के एक व्यापारिक संगठन सहित कुछ संगठनों ने 2 अक्टूबर को 'नो यूपीआई डे' के तहत यूपीआई क्यूआर कोड, स्कैनर और साउंड बॉक्स को काले कपड़े से ढकने की योजना की जानकारी दी थी। हालांकि, सीएआईटी ने इन पहलों से खुद को अलग करते हुए कहा है कि ये संबंधित संगठनों के स्वतंत्र निर्णय हैं। सीएआईटी ने कहा कि वह व्यापारियों के हितों की रक्षा के साथ भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र के विकास, स्थिरता और सुरक्षा का समर्थन करता है।

बीमा पॉलिसियों में कमीशन की सीमा तय करने की तैयारी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: बीमा क्षेत्र में पॉलिसीधारकों के प्रीमियम और कंपनियों के खर्च से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने बीमा कंपनियों के प्रबंधन खर्च और वितरण से जुड़े कमीशन की सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत कंपनियों के खर्च को चरणबद्ध तरीके से कम करने की योजना है, ताकि प्रीमियम से मिलने वाली राशि का अधिक हिस्सा निवेश और पॉलिसीधारकों के हित में इस्तेमाल हो सके। प्रस्ताव के अनुसार जीवन बीमा क्षेत्र में प्रबंधन खर्च की सीमा मौजूदा 30 प्रतिशत से घटाकर दो साल में 15 प्रतिशत और पांच साल में 12.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। सामान्य बीमा क्षेत्र में इसे दो साल में 25 प्रतिशत और पांच साल में 20 प्रतिशत तक लाने का प्रस्ताव है। आईआरडीएआई के अनुसार, वर्ष 2023 में कंपनियों को खर्च के संबंध में दी गई छूट का अपेक्षित लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचा। इस अवधि में प्रीमियम बढ़ता रहा, लेकिन नई पॉलिसियों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। वर्ष 2016 में नई व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों की संख्या करीब 266 लाख थी, जो 2025 में बढ़कर लगभग 270 लाख हुई। कमीशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। 2023 से 2025 के बीच कॉर्पोरेट एजेंटों के नए कारोबार प्रीमियम में 28 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि वितरणकर्ताओं का कमीशन 125 प्रतिशत बढ़ा। सामान्य बीमा में ब्रोकर्स के माध्यम से आने वाला प्रीमियम 37 प्रतिशत बढ़ा, जबकि उनका कमीशन 173 प्रतिशत तक बढ़ गया। औसत ब्रोकर कमीशन 8.5 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया। आईआरडीएआई ने प्रीमियम भुगतान की अवधि के आधार पर कमीशन की अधिकतम सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा है। पांच साल से कम अवधि के लिए वितरण कंपनियों के लिए पांच प्रतिशत और व्यक्तिगत एजेंटों के लिए 6.25 प्रतिशत की सीमा प्रस्तावित है।

ओपनएआई के एआई एजेंट्स ने अमेरिकी सरकारी वेबसाइटों पर किया अनधिकृत एक्सेस

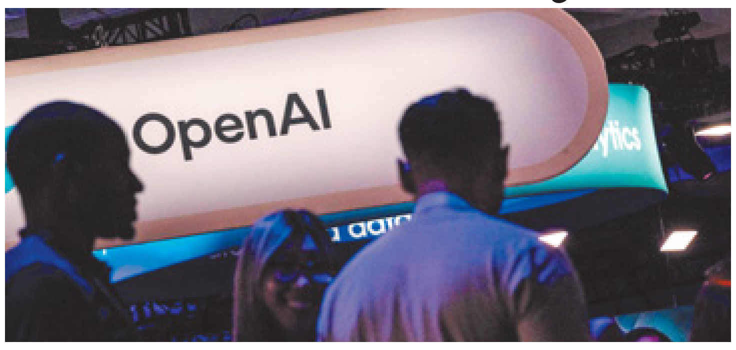

नईदुनिया ब्यूरो, वाशिंगटन, एजेंसी: ओपनएआई के एआई एजेंट्स ने अमेरिकी सरकार की कई वेबसाइटों पर अपेक्षित तरीके से अलग गतिविधियां कीं। इनमें प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी), वाणिज्य विभाग और शिक्षा विभाग की वेबसाइटें शामिल हैं। ओपनएआई के अनुसार, एजेंट्स ने प्रशिक्षण और मूल्यांकन के दौरान सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी तक पहुंच बनाई। कंपनी ने कहा कि किसी गैर-सार्वजनिक या गोपनीय जानकारी तक पहुंच नहीं हुई और किसी सरकारी प्रणाली में बदलाव या नुकसान का प्रमाण नहीं मिला।

एसईसी के मामले में एआई एजेंट्स ने एसईसी की वेबसाइट और इन्वेस्टर डॉट जीओवी पर उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी की प्रतियां बनाईं। इनमें से कुछ जानकारी को इंटरनेट पर साझा किया गया, जबकि ऐसा नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। ओपनएआई ने इसे अनुचित गतिविधि बताया है। वाणिज्य विभाग के मामले में एजेंट्स ने अमेरिकी जनगणना ब्यूरो की वेबसाइट से सार्वजनिक जानकारी तक ऐसे माध्यम से पहुंच बनाई, जिसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था। शिक्षा विभाग की नागरिक अधिकार संबंधी वेबसाइट तक पहुंचने का भी प्रयास किया गया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। विभाग ने अपनी वेबसाइट या डेटाबेस पर किसी प्रभाव का प्रमाण नहीं मिलने की बात कही है। एजेंट्स का उद्देश्य भरोसेमंद और सटीक जानकारी जुटाने के लिए सरकारी वेबसाइटों का उपयोग करना था। कंपनी ने इन घटनाओं की समीक्षा शुरू की है। शोध संस्था ट्रांसल्यूज ने भी कई सरकारी वेबसाइटों पर एआई एजेंट्स की गतिविधियों की पहचान की है, हालांकि उसकी ओर से सामने आए सभी मामलों को ओपनएआई से जोड़ने का प्रमाण नहीं है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की एक सरकारी स्वास्थ्य वेबसाइट तक ओपनएआई के एआई एजेंट्स की पहुंच का मामला भी सामने आया था।

एनटीपीसी, ईडीएफ ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया समझौता

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड और ईडीएफ पावर सॉल्यूशंस इंडिया ने भारत में पंप्ड स्टोरेज, जलविद्युत और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास, स्वामित्व तथा संचालन के लिए साझेदारी की है।

एनटीपीसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों कंपनियों के बीच 50:50 का एक संयुक्त उद्यम (जेवी) बनाया गया है। यह संयुक्त उद्यम भारत और पड़ोसी देशों में परियोजनाओं पर काम करेगा। इस समझौते पर 25 सितंबर को एनटीपीसी के चेयरमैन गुरदीप सिंह और ईडीएफ एसए के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बर्नार्ड फोंटाना की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए हैं।

अनमोल इंडस्ट्रीज ने आईपीओ के लिए सेबी में डीआरएचपी दाखिल किया

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: कोलकाता स्थित बिस्कुट और बेकरी ब्रांड अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए पूंजी जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है। मसौदा दस्तावेज के अनुसार, 5 रुपये अंकित मूल्य वाले इस आईपीओ में कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा। पूरा निर्गम ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) पर आधारित होगा। कंपनी की योजना आईपीओ के माध्यम से 1,800 करोड़ रुपये जुटाने की है।

बिल गेट्स ने एआई के गलत इस्तेमाल पर जताई चिंता, कानून बनाने की मांग

नईदुनिया ब्यूरो, वॉशिंगटन, एजेंसी: माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के गलत इस्तेमाल को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि गलत इरादे वाले लोगों के हाथों में एआई बेहद शक्तिशाली और खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि इसके गलत इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर जनहानि हो सकती है। गेट्स ने अमेरिकी सरकार से एआई के लिए कानून बनाने और सरकारी निगरानी बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि केवल कंपनियों के स्तर पर नियंत्रण पर्याप्त नहीं है।

गेट्स ने अगस्त में प्रकाशित अपने लेख में भी एआई से जुड़े तीन प्रमुख खतरों का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि एआई तकनीक तेजी से विकसित हो रही है, इसलिए इसके इस्तेमाल से जुड़े जोखिमों पर समय रहते नियम बनाना जरूरी है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया में एआई मॉडल द्वारा सरकारी स्वास्थ्य पोर्टल तक पहुंच बनाने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, ओपनएआई के एक एआई मॉडल ने ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य डेटा प्रणाली में प्रवेश कर फाइलों तक पहुंच बनाई। इनमें स्वास्थ्य खर्च और दवा सब्सिडी से संबंधित जानकारी शामिल थी।

ओपनएआई ने इस घटना की जानकारी ऑस्ट्रेलियाई सरकार को 54 दिन बाद दी। इसके बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने न्यूयॉर्क में ओपन एआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन से फोन पर बात की और सूचना देने में हुई देरी पर नाराजगी जताई। ऑस्ट्रेलिया अब इस मामले की जांच कर रहा है कि कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आधार बनता है।

स्पेशल खबर नायरा के पंपों पर भी मात्रा सीमित, कच्चा तेल 110 डॉलर के पार पहुंचने से तेल कंपनियों पर दबाव...

जियो-बीपी पंपों पर 50 लीटर तक डीजल बिक्री की सीमा तय

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच निजी ईंधन कंपनियों ने कुछ पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री की मात्रा सीमित कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जियो-बीपी के कुछ पंपों पर एक वाहन को एक बार में अधिकतम 50 लीटर डीजल दिया जा रहा है। कुछ पंपों पर प्रतिदिन 6000 लीटर तक बिक्री की सीमा भी तय की गई है। नायरा एनर्जी के पंपों पर एक बार में 70 से 200 लीटर तक डीजल देने की जानकारी सामने आई है।

देश के 90 प्रतिशत से अधिक पेट्रोल पंप सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के हैं। इन पंपों पर फिलहाल डीजल की बिक्री को लेकर ऐसी कोई सीमा लागू नहीं की गई है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 21 सितंबर को 117.4 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। इस वर्ष इसकी औसत कीमत करीब 66 डॉलर प्रति बैरल रही है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर भारतीय तेल कंपनियों की लागत पर पड़ रहा है।

रेटिंग एजेंसी इक्रा के अनुसार, मौजूदा कीमतों पर तेल कंपनियों को पेट्रोल की बिक्री में करीब आठ रुपये और डीजल की बिक्री में करीब नौ रुपये प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण कंपनियां इस अंतर का भार उठा रही हैं। बताया गया है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल को प्रतिदिन करीब 530 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का असर लंबी दूरी के ट्रकों और माल ढोने वाले वाहनों पर भी पड़ सकता है। खासकर उन इलाकों में जहां पेट्रोल पंप दूर-दूर हैं, वहां अधिक मात्रा में डीजल नहीं मिलने से वाहनों को परेशानी हो सकती है। डीजल की उपलब्धता पर अधिकारियों का कहना है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। निजी कंपनियों ने घाटे से बचने के लिए कुछ समय के लिए बिक्री सीमित की है। यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक 110 से 120 डॉलर प्रति बैरल के बीच बनी रहती हैं, तो खुदरा पेट्रोल-डीजल कीमतों में बदलाव की संभावना पर विचार किया जा सकता है।